



उज्जैन सोचेमेरा विकास का नंबर क्या अब आएगा?

● मनमोहन शर्मा की रिपोर्ट

क्या उज्जैन विश्व का आध्यात्मिक शहर बन पायेगा? उज्जैन में महाकाल है, तो आने वाला कल ही बता देगा कि क्या होगा? कम ही लोग जानते हैं कि नए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 11 अक्टूबर 2022 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 'श्री महाकाल महालोक' के उद्घाटन से पहले उज्जैन में मध्य प्रदेश कैबिनेट की पहली बैठक की मेजबानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 27 सितंबर 2022 को कैबिनेट की बैठक हुई और दिलचस्प बात यह रही कि पीठासीन अधिकारी के रूप में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंगम का चित्र रखा गया। यादव का मकसद राजा विक्रमादित्य के काल में देश की राजधानी रहे उज्जैन के पुराने गौरव को फिर से स्थापित करना था।

क्या मुख्यमंत्री अपने निर्वाचन क्षेत्र उज्जैन के विकास की नई तस्वीर बना पाएंगे?



उज्जैन का विकास: क्या है नई सरकार का संकल्प?



संकल्प पत्र



अब जब वह सीएम हैं, तो उज्जैन के लोगों को उम्मीद है कि वह अपनी प्रतिबद्धता और 2023 के चुनाव के लिए अपनी पार्टी द्वारा संकल्प पत्र में की गई प्रतिबद्धता को पूरा करने में सक्षम होंगे। उज्जैन के लोगों को उम्मीद है कि वह उज्जैन में औद्योगिकरण की गति बढ़ाएंगे और क्षिप्रा नदी के शुद्धिकरण और सरकारी मेडिकल कॉलेज की स्थापना जैसे ज्वलंत मुद्दे उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होंगे। लेकिन, निश्चित रूप से, उनके सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक अप्रैल-मई 2028 में उज्जैन में सिंहस्थ महापर्व की मेजबानी करना होगा।

उज्जैन टाइम्स आपके लिए सत्तारूढ़ दल द्वारा प्रतिबद्ध उज्जैन जिले का विशेष बिंदुवार एजेंडा लेकर आया है।

संकल्प पत्र में उज्जैन के लिए

- भारत का पहला यूनिटी मॉल- एक जिला-एक उत्पाद-वन स्टॉप मार्केट प्लेस-भारत का पहला यूनिटी मॉल स्थापित किया जाएगा।
- घाट आधुनिकीकरण मिशन- क्षिप्रा के घाटों को आधुनिक बनाया जाएगा और पुनर्जीवित किया जाएगा।
- उज्जैन को ग्लोबल स्पिरिचुअल सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा।
- उज्जैन-चना अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जायेगी।

- मालवा-निमाड़ विकास पथ- 450 किलोमीटर (मंदसौर-इंदौर-उज्जैन-बुरहानपुर को जोड़ा जाएगा)।
- क्षिप्रा महोत्सव हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जायेगा
- क्षिप्रा नदी बेसिन प्राधिकरण बनाया जाएगा।
- उज्जैन-रिंग रोड बनाया जाएगा/स्थापना की जायेगी।
- उज्जैन हवाई पट्टी-पुनर्विकास किया जाएगा।
- हरसिद्धि माता शक्तिपीठ-आधुनिकीकरण एवं पुनर्विकास।
- उज्जैन में मृगनयनी एम्पोरियम स्थापित किया जायेगा।
- उज्जैन स्मार्ट सिटी का विकास समय पर किया जाये।
- प्लग एंड प्ले मॉडल-सब्सिडी आधारित सहकर्मि स्थान विकसित किया जाएगा।
- उज्जैन में मेडिकल डिवाइस पार्क-एमपी फर्स्ट पार्क बनाया जाएगा/स्थापना की जायेगी।
- प्रत्येक सम्भाग में मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (आईआईटी के अनुरूप)।
- प्रत्येक जिले में एक खेल परिसर-एक जिला-एक परिसर।
- प्रत्येक सम्भाग में मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान संस्थान (MPIMS)।
- प्रत्येक लोकसभा में एक मेडिकल कॉलेज होगा।

- हर जिले में नर्सिंग कॉलेज बनाया जाएगा/स्थापना की जायेगी।
- दीदी कैफे- प्रत्येक प्रमुख शहर में।
- प्रत्येक जिले में न्यूनतम एक महिला पुलिस स्टेशन।
- उज्जैन संभाग- मध्य प्रदेश सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना के लिए 200 करोड़ रुपये।
- क्षिप्रा पुलिस बटालियन विकसित की जायेगी।
- प्रत्येक सम्भाग में एक मातृ वंदना सुपर स्पेशलिटी अस्पताल होगा।
- हर जिले में बागवानी हब।
- प्रत्येक जिले में गोवंश विहार।
- प्रत्येक सम्भाग में मध्य प्रदेश प्रौद्योगिकी संस्थान।
- हर जिले में मुफ्त भोजन और साफ पानी के साथ आश्रम शाला विकसित की जाएगी।
- प्रमुख शहर में पिंग बस नेटवर्क

से किए गए उपरोक्त वादों को पूरा प्रशासन/एमपी सरकार के प्रत्येक करने की दिशा में जिला संकल्प की निगरानी करेगा।

सुरक्षा को रखिए बरकरार
सुरक्षा होज़ की
तारीख रखिए याद।

एक्सपायरी डेट करीब
आने पर अपने
होज़ पाइप बदले.
अपने एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर
से संपर्क करें।
जनहित में जारी

सम्पादकीय

पिछले एक साल से विवादों और सुर्खियों में रहने वाले अडानी हिंडनबर्ग मामले का सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से पटाक्षेप कर दिया है। हालांकि, अभी इसे पूरा पटाक्षेप नहीं कहा जाएगा। मगर इस मामले में देश के सबसे बड़े कारोबारी समूह पर जो 24 आरोप लगे थे, उनमें से 22 में 'सेक्यूरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया' यानी सेबी ने अडानी समूह को बेदाग करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार के अपने फैसले में कहा है कि सेबी की रिपोर्ट पर शक करने का कोई कारण नहीं है। समूह के खिलाफ बाकी दो आरोपों की अभी जांच चल रही है, इनमें समय लग रहा है, क्योंकि इनकी जांच का दायरा देश के बाहर जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने तीन महीने में इनकी भी रिपोर्ट देने को कहा है। मुहावरे का इस्तेमाल करें, तो इस मामले में हाथी निकल गया और पूंछ भर बची है। यह मामला पिछले साल जनवरी में तब सुर्खियों में आया था, जब अमेरिका की एक कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी समूह पर आरोप लगाया था कि इसके कारोबार में बहुत से घपले हैं और इस समूह ने अपने शेयरों के दाम बुलंद करने के लिए कई तरह की अनियमितताएं बरती हैं। ये आरोप काफी

संगीन थे और तमाम राजनीतिक कारणों से इन पर काफी हंगामा भी शुरू हो गया है। यहां पर हिंडनबर्ग के कारोबार के तरीके की चर्चा भी जरूरी है। हिंडनबर्ग मुख्य रूप से दुनिया की बड़ी कंपनियों के भंडाफोड़ के लिए जानी जाती है और इसके बाद जब बाजार में उन कंपनियों के शेयरों के भाव गिरते हैं, तो वह उनसे मुनाफा कमाती है। हिंडनबर्ग रिसर्च का पूरा कारोबार यही है। रिपोर्ट सनसनीखेज थी, जिसके जवाब में अडानी समूह ने 413 पेज की अपनी सफाई पेश की। लेकिन जिस पर आरोप लगे हों, उसकी सफाई सुनता ही कौन है? खासकर तब, जब वह मामला राजनीतिक रंग ले चुका हो। बहरहाल, कुछ लोग इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट चले गए और जनहित याचिकाएं डालकर यह मांग करने लगे कि इस मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल, यानी एसआईटी का गठन किया जाए या फिर इसकी जांच सीबीआई जैसी जांच एजेंसी से कराई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच का काम सेबी को सौंपा था और इसके साथ ही जाने-माने विशेषज्ञों की एक कमेटी भी यह

देखने के लिए बना दी थी कि कहीं नियामक इस मामले में नाकाम तो नहीं रहे। सर्वोच्च न्यायालय ने सेबी की जांच रिपोर्ट पर भरोसा जताते हुए कहा कि इस मामले में एसआईटी के गठन की अब कोई जरूरत नहीं है। अदालत की तीन सदस्यीय पीठ ने सेबी से यह भी कहा है कि उसे यह भी पता लगाना चाहिए कि इस विवाद का फायदा उठाकर बाजार में कोई कारोबार या शॉर्ट सेलिंग तो नहीं की गई? साथ ही इसके कारण निवेशकों को नुकसान तो नहीं उठाना पड़ा?

अदालत ने जनहित याचिकाओं पर जो टिप्पणी की है, वह भी काफी महत्वपूर्ण है। अदालत ने कहा है कि ऐसी याचिकाओं के लिए निराधार खबरों और असत्यापित रिपोर्टों को आधार नहीं बनाया जाना चाहिए। अदालत ने यह भी कहा है कि कुछ थर्ड पार्टी रिपोर्ट के आधार पर ही सेबी जैसी संस्था के कामकाज पर सवाल उठाना ठीक नहीं है। उम्मीद है, जनहित याचिका दायर करने वाले भविष्य में इसका ख्याल रखेंगे। उम्मीद यह भी की जानी चाहिए कि इस मामले को लेकर चलने वाला राजनीतिक विवाद भी अब शांत हो जाएगा।

आरबीआई गोल्ड बॉन्ड 2023-24 सीरीज 3-क्या रिटर्न आगे दोहराया जाएगा?

नवंबर 2015 में लॉन्च किए गए, आरबीआई के गोल्ड बॉन्ड सोने के ग्राम में मूल्यवर्गित सरकारी प्रतिभूतियां हैं। वे भौतिक सोने के विकल्प के रूप में काम करते हैं। केंद्र सरकार की ओर से आरबीआई द्वारा जारी एसजीबी का उद्देश्य भौतिक सोने की मांग को कम करना और बचत को बढ़ावा देना है।

पहली स्वर्ण बांड योजना 2015 श्रृंखला I, 2015 में निर्गम मूल्य-2,684/- रुपये प्रति ग्राम सोने के साथ शुरू की गई थी। पहला एसजीबी 30 नवंबर 2015 को जारी किया गया था।

व्यवस्था की शर्तों के अनुसार, बांड जारी होने के 8 साल बाद चुकाए जाने चाहिए। परिणामस्वरूप, 30 नवंबर, 2023 को SGB की पहली किश्त परिपक्व हो गई।

वित्त वर्ष 2023-24

की श्रृंखला-3

6199 रुपये प्रति ग्राम-प्रस्ताव पर नए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की कीमत (वित्त वर्ष 2023-24 की श्रृंखला III), 18-22 दिसंबर 2023 की अवधि के दौरान उपलब्ध है। हमेशा की तरह, ऑनलाइन आवेदन के लिए 50 रुपये की छूट है, यानी आपको यह मिलेगा 6149 रुपये प्रति ग्राम पर।

गोल्ड बांड की पहली किश्त का वास्तविक रिटर्न क्या है?

एसजीबी 2015-I का निर्गम मूल्य 92,684 रुपये प्रति ग्राम सोने पर तय किया गया था, इसी तरह, मोचन मूल्य 6132 के रूप में गणना की गई थी। निवेशकों ने सोने की कीमतों से जुड़ा प्रति यूनिट रिटर्न अर्जित किया।



● मोचन मूल्य-निर्गम मूल्य।

● 6,132 रुपये-2,684 रुपये।

● 3,448 रुपये प्रति यूनिट।

बांड पर प्रति वर्ष 2.75% की निश्चित दर पर ब्याज आय भी प्राप्त होती थी, जिसका भुगतान अर्धवार्षिक रूप से किया जाता था।

● रु. 2,684 2.75% प्रतिवर्ष।

● रु. 73.81 प्रति यूनिट प्रति वर्ष।

● 36.91 रुपये प्रति यूनिट अर्धवार्षिक।

इसलिए, अनुमान है कि गोल्ड बॉन्ड (एसजीबी) सीरीज I ने निवेशकों को इश्यू से परिपक्वता तक 912.9% का एक्सआईआरआर रिटर्न दिलाया है। (ब्याज सहित)।

12.9% का दोहरे अंक का रिटर्न अच्छा है या नहीं, हम नहीं जानते! कृपया दीर्घकालिक निवेश के लिए प्रमाणित वित्तीय पेशेवर से परामर्श लें।

वित्तीय सलाहकार क्यों?

● ज्ञान की कमी और जानकारी की अधिकता से निवेशकों को यह विश्वास हो रहा है कि वे पेशेवर मदद के बिना सब कुछ खुद ही प्रबंधित कर सकते हैं। किसी भी मुफ्त चीज की

कीमत लंबे समय में दोगुनी हो जाती है या वह बेकार हो जाती है।

● इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन लिमिटेड (आईबीजे) की रिपोर्ट के अनुसार, एसजीबी के मोचन मूल्य की गणना मोचन तिथि से पहले के सप्ताह में 999 शुद्धता वाले सोने के समापन मूल्य के साधारण औसत के रूप में की जाती है, यानी 2024 नवंबर 2023 के बीच।

● परिपक्वता तक रखे जाने पर एसजीबी को पूंजीगत लाभ कर से छूट मिलती है। हालांकि, ब्याज आय व्यक्तिगत आयकर स्लैब के अनुसार कर योग्य होगी।

क्या सोने के लिए पिछले 8 सालों में सफर आसान रहा?

● सोने की पिछले 8 वर्षों की सपाट और ऊबड़-खाबड़ यात्रा पर ध्यान दें। 2015 से 2019 तक यह एक प्रवृत्ति थी और 2019 से आगे की प्रवृत्ति थी लेकिन अगले चार वर्षों के लिए सीमाबद्ध के भीतर।

सोने में निवेश के बारे में कुछ तथ्य

● सोना खरीदना और सोने में निवेश करना दो अलग-अलग चीजें हैं। गहराई से समझने के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें।

● अगर कोई व्यक्ति सोना



खरीदना चाहता है तो एक बार में बहुत सारा सोना न खरीदना ही समझदारी है। सोने में निवेश को एक निश्चित अवधि में फैलाना सबसे अच्छा है।

● स्टॉक और बॉन्ड के विपरीत, सोने का कोई आंतरिक मूल्य या नकदी प्रवाह नहीं होता है। इसलिए मूल्यांकन की अवधारणा बिल्कुल लागू नहीं है।

● भारत में सोने में निवेश के

लिए कई विकल्प उपलब्ध हैं। जैसे गोल्ड ईटीएफ, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (एसजीबी या गोल्ड बॉन्ड) और गोल्ड फंड।

● सोना आपके पोर्टफोलियो में विविधता लाने वाला और एक तरह का बचाव है।

यह आम तौर पर पोर्टफोलियो का मूल नहीं होना चाहिए।

घर-घर पहुंचा श्री रामलला प्राण-प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण

भोपाल। अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान श्री रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा का समारोह आयोजित किया जा रहा है। इसको लेकर रामभक्तों द्वारा अयोध्या जाने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद विष्णुदत्त शर्मा, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद ने भोपाल के अलग-अलग कॉलोनियों में घर-घर सम्पर्क कर लोगों को अक्षत देकर अयोध्या जाने के लिए आमंत्रित किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष शर्मा ने वार्ड-28 के अम्बेडकर नगर में श्रीराम भक्तों द्वारा चलाए जा रहे अक्षत वितरण गृह संपर्क अभियान में शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन



यादव ने गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र के वार्ड-72 स्थित पारसधाम कॉलोनी, भानपुर में घर-घर जाकर अक्षत वितरित कर लोगों को अयोध्या जाने का आमंत्रण दिया। वहीं पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद ने नरेला विधानसभा क्षेत्र के अशोका गार्डन में गृह संपर्क अभियान के तहत अक्षत देकर रहवासियों को भगवान राम के दर्शन करने अयोध्या जाने के लिए आमंत्रित किया है।



वैदिक घड़ी के अंकों का अर्थ



उज्जैन में बन रही है पहली वैदिक घड़ी

उज्जैन को मिलेगी दुनिया की पहली वैदिक घड़ी, लोकार्पण 2 अप्रैल 2024 को हिंदू नववर्ष चैत्र प्रतिपदा के दिन किया जाएगा

इस घड़ी को लखनऊ की संस्था आरोहण के आरोह श्रीवास्तव द्वारा डिजिटल तकनीक से बनाया जा रहा है। उक्त घड़ी में परंपरागत घड़ियों के जैसे कल पुर्जे नहीं रहेंगे।

कहा गया है कि लोग घड़ी के बैकग्राउंड में हर घंटे तस्वीर बदलते देख पाएंगे। एक वक्त में द्वादश ज्योतिर्लिंग मंदिर, नवग्रह, राशि चक्र दिखाई देंगे तो दूसरे वक्त देश-दुनिया में होने वाले सबसे खूबसूरत सूर्यास्त, सूर्य ग्रहण के नजारे दिखाई देंगे।

इस प्रोजेक्ट के जरिए लोग वैदिक काल गणना से परिचित हो सकेंगे। राज्य सरकार ने इस मेगा परियोजना के लिए 1.62 करोड़ रुपये आवंटित किए थे क्योंकि यह उज्जैन के प्राचीन गौरव को बहाल करने के लिए काम कर रहा है। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी को 24 मुहूर्त (घंटे) में विभाजित किया जाएगा। विश्व की पहली वैदिक घड़ी सूर्योदय के आधार पर समय की गणना करेगी। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को भारतीय समय गणना से परिचित कराना है।

घड़ी के लिए विक्रमादित्य वैदिक घड़ी मोबाइल एप जारी किया जाएगा। वैदिक घड़ी का प्रयोग विक्रम पंचांग, विक्रम संवत् माह, ग्रह स्थिति, योग, भद्रा स्थिति, चंद्र स्थिति, त्योहार, शुभ समय, नक्षत्र, जयंती, व्रत, त्योहार, चौघड़िया, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, प्रमुख के लिए होगा। छुट्टियाँ, आकाशीय ग्रह, नक्षत्र और धूमकेतु आदि।

उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य ने विक्रम संवत् की शुरुआत की थी

उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य ने विक्रम संवत् की शुरुआत की थी। सम्राट विक्रमादित्य शोध पीठ के निदेशक डॉ. श्रीराम ने विश्वास जताया कि वैदिक घड़ी लगने के बाद उज्जैन का प्राचीन गौरव लौटेगा और दुनिया के इतिहास में फिर से इस नगरी का नाम दर्ज होगा। उज्जैन के बाद देश के दूसरे प्रमुख शहरों में भी वैदिक घड़ी लगाने की योजना बनाई जाएगी।

हर अंक का रहस्य वैदिक घड़ी के हर अंक में हिंदू धर्म से जुड़े कई रहस्य छिपे हैं। जैसे....

उज्जैन। महाकाल की नगरी, जल्द ही दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का दावा करेगी, जो सूर्य की स्थिति के साथ समन्वयित होगी। घड़ी की खास बात यह है कि घड़ी ग्रीनविच (24 घंटे समय) पद्धति और हिंदू कालगणना के अनुसार 30 घंटे की समय पद्धति को एकसाथ दर्शाएगी। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि, उज्जैन के वर्तमान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 7 नवंबर 2022 को उज्जैन में 300 साल पुरानी जीवाजी वेधशाला की आधारशिला रखी थी। वैदिक घड़ी की लागत करीब 1 करोड़ 62 लाख रूपए अनुमानित हैं। वैदिक घड़ी इंटरनेट और जीपीएस से जुड़ी होगी, जिसके कारण कहीं भी इसका उपयोग किया जा सकेगा।

- 12 बजने के स्थान पर आदित्या-लिखा है, जिसका मतलब है कि सूर्य 12 प्रकार के होते हैं- अंशुमान, अर्यमन, इंद्र, त्वष्टा, धातु, पर्जन्य, पूषा, भग, मित्र, वरुण, विवस्वान और विष्णु।
- 1 के स्थान पर ब्रह्म लिखा है, जो बताता है कि ब्रह्म एक है।
- 2 की जगह अश्विनौ, जिसका अर्थ

- है कि अश्विनी कुमार दो हैं- नासत्य और दस्रत्र।
- 3 की जगह त्रिगुणा-लिखा है, जो तीन गुणों सतो, रजो और तमो को निर्दिष्ट करता है।
- 4 के स्थान पर चतुर्वेदा-यह बताता है कि वेद चार हैं।
- 5 बजे पंचप्राणा-का अर्थ है कि प्राण पांच प्रकार के हैं-अपान,

- समान, प्राण, उदान और व्यान।
- 6 के स्थान पर षड्सा-लिखने का मतलब है कि रस 6 प्रकार के होते हैं-मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कसाय।
- 7 बजे सप्तर्षय-यानी ऋषि सात हैं- कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ।

8 के स्थान पर अष्ट सिद्धिय- लिखने का मतलब है कि सिद्धियां आठ प्रकार की होती हैं। ये हैं- अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इशित्व और वशित्व।

9 के स्थान पर नवद्रव्याणि अभियान का तात्पर्य है निधियां 9 हैं- पद्म, महापद्म, नील, शंख, मुकुंद, नंद, मकर, कच्छप, खर्व।

10 की जगह दशदिशः 10 दिशाओं की ओर इंगित करता है।

11 के स्थान पर रुद्र-लिखा है, जो बताता है कि रुद्र 11 हैं- कपाली, पिंगल, भीम, विरुपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, अहिर्बुध्न्य, शम्भु, चण्ड और भव।

राष्ट्रीय पर्यटन नीति 2023 अर्थव्यवस्था के लिए प्रेरक शक्ति

पर्यटन को दुनिया भर में किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए एक प्रमुख प्रेरक शक्ति के रूप में देखा जाता है। आतिथ्य सत्कार जैसे संबद्ध उद्योगों पर इसका कई गुना प्रभाव पड़ता है। पर्यटन से होने वाली कमाई को अन्य उद्योगों में स्थानांतरित करने से न केवल आर्थिक स्थिति में सुधार होता है, बल्कि स्थानीय आबादी के जीवन स्तर में भी सुधार होता है। लेकिन भारत में पर्यटन क्षेत्र से जुड़ी कई चुनौतियाँ हैं, जैसे बुनियादी ढांचागत कमी, अस्थिरता, जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण।

जबकि भारत जी20 की अध्यक्षता संभालता है और 2023 में शिखर सम्मेलन की तैयारी शुरू करता है, देश को एक सुरक्षित, पर्यटक-अनुकूल गंतव्य के रूप में स्थापित करना इस बात पर निर्भर करता है कि सरकार उद्योग के साथ मिलकर कैसे काम कर सकती है और आने वाले गणमान्य व्यक्तियों को विश्व स्तरीय अनुभव प्रदान कर सकती है।

पर्यटन मंत्रालय ने हाल के विभिन्न विकासों के आधार पर एक राष्ट्रीय पर्यटन नीति का मसौदा तैयार किया। नीति का उद्देश्य देश में पर्यटन विकास के लिए रूपरेखा स्थितियों में



सुधार करना, पर्यटन उद्योगों का समर्थन करना, पर्यटन सहायता कार्यों को मजबूत करना और पर्यटन उप क्षेत्रों का विकास करना है। नीति के प्रमुख रणनीतिक उद्देश्य हैं-

1. यात्रा, प्रवास और खर्च को बढ़ाकर और भारत को साल भर पर्यटन स्थल बनाकर भारतीय अर्थव्यवस्था में पर्यटन के योगदान को बढ़ाना।
2. पर्यटन क्षेत्र में रोजगार और उद्यमशीलता के अवसर पैदा करना और कुशल कार्यबल की आपूर्ति सुनिश्चित करना।

3. पर्यटन क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करने के लिए

4. देश की सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एवं संवर्धन करना।

5. देश में पर्यटन का सतत, जिम्मेदार और समावेशी विकास सुनिश्चित करना।

यह नीति विकास के लिए समग्र दृष्टिकोण, मार्गदर्शन और दिशा प्रदान करने के लिए केंद्रीय पर्यटन मंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय पर्यटन

सलाहकार परिषद (एनटीएसी) का प्रावधान करती है, जिसमें राज्यों के सभी पर्यटन मंत्री, संबंधित संबंधित मंत्रालयों के प्रतिनिधि और उद्योग हितधारक शामिल होते हैं।

यह नीति पर्यटन उद्योग के सामने आने वाली प्रमुख और बहुआयामी चुनौतियों का समाधान करने और देश में पर्यटन क्षेत्र को विकसित करने के लिए केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों के साथ-साथ केंद्र और राज्य सरकारों के बीच एक संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण का पालन करती है।

पद्म सम्मान : वापसी जैसी कोई बात नहीं

ये सम्मान गृह मंत्रालय की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाते हैं

पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है, जिसकी घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर की जाती है

पुरस्कार तीन श्रेणियों में दिए जाते हैं

- पद्म विभूषण (असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए)।
- पद्म भूषण (उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा)।
- पद्म श्री (प्रतिष्ठित सेवा)।

यह पुरस्कार गतिविधियों या विषयों के उन सभी क्षेत्रों में उपलब्धियों को मान्यता देना चाहता है जहां सार्वजनिक सेवा का एक तत्व शामिल है।

पद्म पुरस्कार समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर प्रदान किए जाते हैं, जिसका गठन हर साल प्रधान मंत्री द्वारा किया जाता है। नामांकन प्रक्रिया जनता के लिए खुली है। यहां तक कि स्व-नामांकन भी किया जा सकता है। जाति, व्यवसाय, पद या लिंग के भेदभाव के बिना सभी व्यक्ति इन पुरस्कारों के लिए पात्र हैं। हालांकि, डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को छोड़कर, PS के साथ काम करने वाले

सरकारी कर्मचारी इन पुरस्कारों के लिए पात्र नहीं हैं।

पद्मश्री लौटाने का पहलवान



बजरंग पूनिया का निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि नियम कहते हैं कि पद्म सम्मान में वापसी जैसा कोई प्रावधान नहीं है। इन्हें वापस नहीं किया जा सकता। इससे पहले भी कई विशिष्ट व्यक्तियों ने विरोधस्वरूप अपने पद्म सम्मानों को वापस करने का निर्णय किया। लेकिन पद्म सम्मान में वापसी जैसी कोई बात नहीं है। ये सम्मान गृह

मंत्रालय की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाते हैं।

टाइम्स ऑफ इंडिया के समाचार



के अनुसार पद्म सम्मानों का रजिस्टर होता है जिसमें सम्मान मिलने वालों के कहने पर नाम हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। पद्म सम्मान पाने वालों का नाम भारतीय गजट में प्रकाशित होता है। यानी एक बार सम्मान मिला तो आजीवन रहता है। यहां तक कि मृत्यु पश्चात भी व्यक्ति पद्म सम्मानित ही कहा जाएगा।

हां। यह अवश्य है कि अगर राष्ट्रपति चाहें तो वे किसी व्यक्ति को दिए पद्म सम्मान को बाद में रद्द कर

की पृष्ठभूमि की छानबीन होती है। संबंधित व्यक्ति की रजामंदी भी ली जाती है।

आपको याद होगा कुछ ऐसे मामले भी हुए जब कुछ लोगों ने सरकार की पद्म सम्मान की पेशकश को ठुकरा दिया। लेकिन एक बार जब मिल जाता है तो हमेशा के लिए रहता है।

राष्ट्रपति को पत्र लिखने के बाद भी नहीं हटा नाम

बता दें कि पद्म पुरस्कारों की लौटाने वालों की सूची में पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल और पूर्व केंद्रीय मंत्री एसएस ढींडसा भी शामिल हैं। उन्होंने 2020 में राष्ट्रपति को लिखे पत्र में कहा था कि वे 3 कृषि कानूनों के खिलाफ हैं और किसानों के साथ एकजुटता दिखाते हुए पुरस्कार वापस कर रहे हैं। इसके बावजूद उनका नाम आज तक भी पद्म पुरस्कार विजेताओं की लिस्ट में है।

क्रिप्टोकॉरेंसी की ट्रेडिंग वाले 9 प्लेटफॉर्म गैरकानूनी घोषित

वित्त मंत्रालय ने नोटिस भेजा है। साथ ही इनके URL को ब्लॉक करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeiTY) को चिट्ठी लिखी गई है। कल से, भारत में इन एक्सचेंजों के लिए संभावित ट्रेडिंग वॉल्यूम में गिरावट और परिचालन चुनौतियां होंगी।

प्रमुख रूप से इनमें Binance, Kucoin, Bittre&, Bitfine&, Huobi शामिल हैं।

1. फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया (FIU IND) ने नौ ऑफशोर वर्चुअल डिजिटल एसेट्स सर्विस प्रोवाइडर्स (VDA SPs) को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

2. FIU IND ने भारत में PMLA अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन किए बिना अवैध रूप से संचालित होने वाली 9 संस्थाओं के (RL) यूआरएल को ब्लॉक करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को लिखा है।

3. वर्चुअल डिजिटल एसेट्स सर्विस प्रोवाइडर्स (VDA SPs) को मार्च 2023 में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत एंटी



मनी लॉन्ड्रिंग/काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म (AML-CFT) ढांचे के दायरे में लाया गया था।

4. OFF SHORE संस्थाओं के खिलाफ अनुपालन कार्रवाई के हिस्से के रूप में, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया (FIU IND) ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 PMLA की धारा 13 के तहत निम्नलिखित 9 ऑफशोर वर्चुअल डिजिटल एसेट्स सर्विस प्रोवाइडर्स (VDA SPs) को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

5. Binance, Kucoi, Huobi, Kraken/Gate.io/

Bittre&, Bitstamp, MEXC Global/ Bitfine&.

6. FIU IND के निदेशक ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव को उन संस्थाओं के URL को ब्लॉक करने के लिए लिखा है जो भारत में PMLA अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन किए बिना अवैध रूप से काम कर रहे हैं।

7. वर्चुअल डिजिटल एसेट्स सर्विस प्रोवाइडर्स (VDA SPs) भारत में काम कर रहे हैं (ऑफशोर और ऑनशोर दोनों) और वर्चुअल डिजिटल एसेट्स और फिएट मुद्राओं

के बीच आदान-प्रदान, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के हस्तांतरण, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स या उपकरणों को सुरक्षित रखने या नियंत्रण करने में सक्षम बनाने जैसी गतिविधियों में लगे हुए हैं।

8. वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों आदि को रिपोर्टिंग इकाई के रूप में FIU IND के साथ पंजीकृत होना आवश्यक है और धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) 2002 के तहत अनिवार्य दायित्वों के सेट का अनुपालन करना आवश्यक है।

9. Regulation PMLA

अधिनियम के तहत VDA SPs पर रिपोर्टिंग, रिकॉर्ड रखने और अन्य दायित्व डालता है जिसमें FIN IND के साथ पंजीकरण भी शामिल है।

10. अब तक 31 वीडिए एसपी ने FIN INDA के साथ पंजीकरण कराया है। हालांकि, कई अपतटीय संस्थाएँ भारतीय उपयोगकर्ताओं के एक बड़े हिस्से को सेवा प्रदान करने के बावजूद पंजीकृत नहीं हो रही थीं और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग (AML) और काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म (सीएफटी) ढांचे के तहत नहीं आ रही थीं।

रानी दुर्गावती का समर्पण और गोंडवाना साम्राज्य का गौरवशाली इतिहास

● डॉ मोहन यादव

मध्यप्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर का इतिहास में गौरवशाली स्थान है। जबलपुर का उल्लेख हर युग में मिलता है। यह वैदिक काल में जाबालि ऋषि की तपोस्थली रही है। हम मध्यकाल में देखें तो जबलपुर का संघर्ष अद्वितीय रहा है। प्रत्येक हमलावर का उत्तर इस क्षेत्र के निवासियों ने वीरतापूर्वक दिया है और यही वीरता वीरांगना रानी दुर्गावती के संघर्ष और बलिदान की गाथा में है। जबलपुर उनके बलिदान की पवित्र भूमि है। अकबर की विशाल सेना से रानी दुर्गावती ने इसी क्षेत्र में मोर्चा लिया था। वीरांगना दुर्गावती का युद्ध कौशल, शौर्य और पराक्रम इससे पूर्व कालिंजर में भी देखने को मिलता है। रानी दुर्गावती के 500वें जन्मशताब्दी अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जनजातीय समाज के कल्याण और समृद्धि के लिए जो संकल्प लिया है उसे पूर्ण करने के लिये मध्यप्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रही है। रानी दुर्गावती, सुशासन व्यवस्था और स्वर्णिम प्रशासन के लिए प्रसिद्ध थीं, जो इतिहास का प्रेरक अध्याय है। यह हमारे लिए प्रसन्नता की बात है कि जबलपुर में नवगठित मंत्रिमंडल की प्रथम कैबिनेट बैठक रानी दुर्गावती की सुशासन नगरी में रखी गई है।



कालिंजर के चंदेल राजा कीरत सिंह शालिवाहन के यहां 05 अक्टूबर सन् 1524 को जन्मी रानी दुर्गावती शस्त्र और शास्त्र विद्या में बचपन में ही दक्ष हो गयी थीं। युद्ध और पराक्रम के वीरोचित किस्से, कार्य-व्यवहार को देखते हुए वे बड़ी हुई।

महोबा की चंदेल राजकुमारी सन् 1542 में गोंडवाना के राजा दलपत शाह से विवाह के उपरांत जबलपुर आ गयीं। तत्समय गोंडवाना साम्राज्य में जबलपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, भोपाल, होशंगाबाद (अब नर्मदापुरम), बिलासपुर, डिंडौरी, मंडला, नरसिंहपुरतथा नागपुर शामिल थे।

जब इस विशाल राज्य के राजा दलपतशाह की असमय मृत्यु हो गयी तो प्रजावत्सल रानी ने विचलित हुए बिना अपने बालक वीर नारायण को गद्दी पर बैठाकर राजकाज संभाला। लगभग 16 वर्षों के शासन प्रबंध में रानी ने अनेक निर्माण कार्य करवाए। रानी की दूरदर्शिता और प्रजा के कल्याण के प्रति संकल्पित होने का प्रमाण है कि उन्होंने अपने निर्माण कार्यों में जलाशयों, पुलों और मार्गोंको प्राथमिकता दी, जिससे नर्मदा किनारे के सुदूर वनों की उपज का व्यापार हो सके और जलाशयों से किसान सिंचाई के लिए पानी प्राप्त कर सके। जबलपुर में रानीताल, चेरीताल, आधारताल जैसे अद्भुत निर्माण रानी की दूरदर्शिता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिणाम है। रानी दुर्गावती के शासन में नारी की सुरक्षा और सम्मान उत्कर्ष पर था। राज्य की सुरक्षा के लिए रानी ने कई किलों का निर्माण करवाया और जीर्णोद्धार भी किया। कृषि तथा व्यवसाय के लिए उनके संरक्षण का ही परिणाम था कि गोंडवाना समृद्ध राज्य बना, लोग लगान स्वर्ण मुद्राओं में चुकाते थे। न्याय और समाज व्यवस्था के लिए हजारों गांवों में रानी के प्रतिनिधि रहते थे। प्रजा की बात रानी स्वयं सुनती थीं।

प्रगतिशील, न्यायप्रिय रानी ने राज्य विस्तार के लिए कभी आक्रमण नहीं किये, लेकिन मालवा के बाज बहादुर द्वारा किये गये हमलों में उसे पराजित किया। गोंडवाना राज्य की संपन्नता, रानी की शासन व्यवस्था,

रणकौशल और शौर्य की साख ने अकबर को विचलित कर दिया। अकबर ने आसफ खां के नेतृत्व में तोप, गोलों औरबारूद से समृद्ध विशाल सेना का दल भेजा और गोंडवाना राज्य पर हमला कर दिया।

रानी दुर्गावती के सामने दो ही विकल्प थे। एक सम्पूर्ण समर्पण और दूसरा सम्पूर्ण विनाश। स्वाभिमानी रानी ने स्वतंत्रता की रक्षा के लिए शस्त्र उठा लिए। वे कहा करती थीं- 'जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु है, जिसे कल स्वीकार करना हो वह आज ही सही।' इसी उद्घोष के साथ उन्होंने हाथ में तलवार लेकर विंध्य की पहाड़ियों पर मोर्चा लिया। आसफ खां का यह दूसरा आक्रमण था। पूर्व में वह पराजित हुआ

था। इस भीषण संग्राम में जबलपुर के बारहा ग्राम के पास नरई नाला के निकट तोपों की मार से जब गोंडवाना की सेना पीछे हटने लगी तो नाले की बाढ़ ने रास्ता रोक दिया। रानी वस्तुस्थिति को समझ गयीं, उन्होंने स्वत्व और स्वाभिमान के लिए स्वयं को कटार घोंपकर आत्मबलिदान दिया।

रानी दुर्गावती स्वाभिमान और स्वतंत्रता का प्रतीक हैं। वीरांगना दुर्गावती ने बलिदान की जिस परंपरा की शुरुआत की, उस पथ का कई वीरांगनाओं ने अनुसरण किया। रानी दुर्गावती के वंशज राजा शंकरशाह और उनके पुत्र रघुनाथशाह को 1857 के महासंग्राम में शामिल होने और कविता

लिखने पर अंग्रेजों ने तोप से उड़ा दिया था। राजा शंकरशाह की पत्नी गोंड रानी फूलकुंवर ने पति व पुत्र के अवशेषों को एकत्र कर दाह संस्कार किया और 52वीं इंफैंट्री के क्रांतिकारी सिपाहियों को लेकर अपने क्षेत्र से सन् 1857 के युद्ध का नेतृत्व किया। अंत में रणभूमि में शत्रु से घिर जाने पर रानी फूलकुंवर ने स्वयं को कटार घोंप ली। गोंडवाना राज्य की पीढ़ियों ने भारत माता की स्वतंत्रता और स्वाभिमान के लिए रानी दुर्गावती की बलिदानी परंपरा को आगे बढ़ाया। राष्ट्र रक्षा, स्वाभिमान और स्वतंत्रता के लिए वीरांगना रानी दुर्गावती और उनके वंशजों के बलिदान पर आने वाली पीढ़ियां सदैव गर्व करेंगी।

नागरिकों को आवश्यक सामग्री के लिए परेशानी न हो, सभी जरूरी उपाय किए जाएं-मुख्यमंत्री

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रालय में कमिश्नर, कलेक्टर और एसपी के साथ वीसी के माध्यम से चर्चा कर ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल के मद्देनजर किए जा रहे आवश्यक उपायों की जानकारी प्राप्त की और जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नागरिकों को आवश्यक सामग्री के लिए परेशानी नहीं हो, इसके लिए सभी जरूरी उपाय किए जाएं।



मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में पेट्रोल-डीजल की सप्लाई प्रभावित न हो। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पेट्रोल-डीजल को लेकर कोई अवरोध पैदा करेगा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए जाएं, जनता को किसी भी प्रकार का कष्ट न हो। पेट्रोल पंप और एलपीजी गैस के डीलर्स जिनके

अपने वाहन हैं, उनके माध्यम से सप्लाई सुनिश्चित की जाए।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जबलपुर, ग्वालियर, कटनी, रीवा, उज्जैन, सागर समेत विभिन्न जिलों के कलेक्टर, एसपी से चर्चा करते हुए कहा कि किसी भी मार्ग पर अवरोध और बाधा न हो। रास्ते की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करें। सभी डीलर्स, एसोसिएशन के साथ बैठक

करें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारा मैदान में मूवमेंट दिखे। सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आदि प्लेटफार्म का उपयोग करते हुए स्थिति सामान्य होने की जानकारी दी जाए। बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा, डीजीपी सुधीर कुमार सक्सेना, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव राघवेंद्र सिंह सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

नैनीताल यात्रा एक सुखद अनुभव....

शेष पृष्ठ 4 से निरंतर..

डिग्री का जादू जो सर चढ़कर बोल रहा था। हमें एक रात और यहां स्टे करना था। इसलिए दोपहर 11 बजे स्नान आदि से निवृत्त होकर नीचे की तरफ जाने लगे तो वहां के केयरटेकर ने कहा कि साहब जीप के बजाय पैदल यात्रा करेंगे तो ज्यादा आनंद आएगा।

पैदल पहाड़ उतरना

लगभग सभी लोग साठ की उम्र के ऊपर थे। फिर भी मित्रों ने कहा कि चलो देखते हैं। उतरने लगे। पगडंडी सुरक्षित थी हालांकि साइड में खाई साथ-साथ चल रही थी। कोई 30 मिनट लगे होंगे हमें ऊपर से नीचे उतरने में बीच-बीच में हंसी मजाक और वीडियो बनाते जा रहे थे और धीरे-धीरे नीचे उतरकर सड़क तक पहुंच गए। यह वही सड़क थी जिससे थोड़ी दूर पर हमने जीप से चढ़ाई की थी। प्रकृति के इतने निकट होकर और जंगलों से बीच गुजरकर नीचे उतरने ने हमें आनंदित कर दिया। नीचे टैक्सी इंतजार कर रही थी। फिर हम नैनीताल गए। फिर नैना देवी के दर्शन किए, नैनीताल झील में बोटिंग की और अच्छी तरह से नैनीताल के आसपास के मार्केट को एक्सप्लोर करके फिर फोर व्हील जीप से हरियाल 360 जाकर रुक गए। हरियाल 360 डिग्री में दूसरे दिन की रात फिर से आनंद से गुजारने के लिए हम शाम 7 बजे से ही अपने रिजॉर्ट पर आ गए थे। रिजोर्ट के आसपास के जंगलों से होकर गुजरे, रिलैक्स किया लॉन में बैठकर चाय का लुत्फ लिया। शाम को घर लोट रहे पक्षियों का कलरव सुना। सुबह रवानगी का टाइम आ गया था। हरियाल के इस रिजॉर्ट को छोड़ने का मन नहीं हो रहा था। लेकिन यात्राएं होती ही ऐसी है।

यात्राओं में जाने के पहले ही लौटने का समय नियत होता है। नियत समय के चलते हम लोग पहाड़ से नीचे उतरे, काठगोदाम तक टैक्सी से आए। यहां से शताब्दी एक्सप्रेस से दिल्ली और दिल्ली से इंदौर नई दिल्ली इंटरसिटी से उज्जैन पहुंच गए।

सच कहूं तो आज तक जितने भी हिल स्टेशनों की यात्रा की है उनमें सबसे सुखद, सुंदर व शांत मुझे नैनीताल लगा है। मुझे ही नहीं मेरे मित्रों मनोहर सोनी, अंगद सिंह राठौर और हम तीनों की पत्नियों की भी यही राय थी। सभी सोच रहे थे कि एक बार और अवसर मिला तो फिर से हरियाल जाकर नाइट स्टे करेंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता नहीं। नैनीताल की यात्रा प्रसन्नता देने वाली है। हर एक पर्यटन प्रेमी को यहां एक बार जाना चाहिए।

लेखक-हरिशंकर शर्मा, उज्जैन
Editor-www.apani-bat.com

इंदौर जिले में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी की आपूर्ति सतत बनाए रखने के लिए

इंदौर। कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में इंदौर जिले में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी की आपूर्ति सतत बनाए रखने के लिए अपर कलेक्टर गौरव बैनल ने ऑयल कंपनी बीपीसीएल, आईओसीएल, एचपीसीएल, टैंकर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, ड्राइवर यूनियन डिपो, पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन, आरटिओ, पुलिस इत्यादि के साथ बैठक की। बैठक में सभी को पेट्रोल, डीजल, एलपीजी की आपूर्ति बनाए रखने के लिए कहा गया।

बैठक में ड्राइवर यूनियन ट्रांसपोर्ट यूनियन को सुना गया, उनकी भ्रातियों का निराकरण भी किया गया। उन्हें समझाइश दी गई कि किसी के बहकावे में न आएं। किसी भी प्रकार का विरोध है, तो ज्ञापन प्रस्तुत करके लिखित में जिला प्रशासन को प्रस्तुत करें, उनकी मांग को शासन में उच्च स्तर तक उचित कार्रवाई के लिए तत्काल भेजा



जाएगा।

इंदौर ऑपरेटर एवं ट्रक एसोसिएशन के सीएल मुकाती ने भी समझाइश दी कि अभी अधिकृत किसी प्रकार की हड़ताल नहीं की गई है, कृपया आम जनता की सुविधा के लिए निर्बाध रूप से डीजल, पेट्रोल, एलपीजी का परिवहन निरंतर करते रहें। तत्पश्चात सभी ड्राइवर और टैंकर लॉरी के ट्रांसपोर्टर काम पर लोटे। आम जनता को किसी प्रकार की परेशानी न

हो, इसके लिए पेट्रोल, डीजल की सतत आपूर्ति बनाए रखने के लिए तत्काल काम शुरू कराया गया और अभी तक 100 से ज्यादा टैंकर पेट्रोल डीजल लेकर निकल चुके हैं। कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी. द्वारा सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि आम जनता को पेट्रोल, डीजल, एलपीजी की आपूर्ति किसी प्रकार भी बाधित न हो इसका विशेष ध्यान रखा जाए।

उज्जैन के नवागत कलेक्टर ने बाबा महाकाल के किये दर्शन

उज्जैन। उज्जैन के नवागत कलेक्टर नीरज सिंह मंगलवार सुबह श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन कर पूजन किया। बाबा महाकाल के दर्शन करने के पश्चात कलेक्टर नीरज सिंह ने प्रशासनिक कार्यालय पहुंचकर पदभार ग्रहण किया।



कलेक्टर नीरज सिंह मंगलवार सुबह श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे और भगवान श्री महाकालेश्वर जी का दर्शन पूजन किया। पूजा प्रक्रिया मंदिर प्रबंध समिति के पूर्व सदस्य व पुजारी राजेश शर्मा द्वारा सम्पन्न कराई गई। विधि विधान से पूजा करने के बाद कलेक्टर नीरज सिंह ने नंदी के कान में अपनी मनोकामना बोलकर आशीर्वाद मांगा। मंदिर प्रबंध समिति के प्रशासक संदीप सोनी द्वारा नीरज सिंह का दुपट्टे, प्रसाद व भगवान श्री महाकाल की फोटो प्रदान कर सम्मान किया गया।

वाहन चालकों की हड़ताल के मद्देनजर संभागायुक्त और आईजी ने बैठक की



उज्जैन। वाहन चालकों की हड़ताल के मद्देनजर संभागायुक्त डॉ. संजय गोयल और आईजी श्री संतोष कुमार सिंह ने प्रशासनिक संकुल भवन के द्वितीय तल स्थित सभाकक्ष में रिटेल और थोक सब्जी, फल, अनाज मंडी, बस ऑपरेटर संघ के ट्रांसपोर्टर्स के साथ बैठक की।

बैठक में संभागायुक्त डॉ. गोयल ने कहा कि संभाग में अत्यावश्यक सेवाओं की आपूर्ति निर्बाध रूप से जारी रहे, यह सुनिश्चित किया जाये। सोशल मीडिया ग्रुप पर किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दिया जाये। साथ ही ऐसी अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जाये। शासकीय बसों का संचालन निरन्तर किया जाये। आमजन को किसी भी तरह की असुविधा या परेशानी न हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये।

बैठक में जानकारी दी गई कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है तथा उनकी आपूर्ति भी निरन्तर की जा रही है। अत्यावश्यक वस्तुओं के परिवहन को सुरक्षा उपलब्ध कराई जायेगी। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी निरन्तर क्षेत्रों में भ्रमण करेंगे। किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति निर्मित होने पर सम्बन्धित के विरुद्ध कार्यवाही भी की

जायेगी। अत्यावश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के मद्देनजर किसी भी तरह की समस्या अथवा शिकायत दर्ज करने के लिये कंट्रोल रूम प्रारम्भ किया गया है। कंट्रोल रूम में 0734-2513512 पर सम्पर्क किया जा सकता है। शासकीय और संविदा कर्मचारी हड़ताल में लिप्त न हो। बैठक में कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम, पुलिस अधीक्षक श्री सचिन शर्मा, नगर निगम आयुक्त श्री रोशन कुमार सिंह, सीईओ जिला पंचायत श्री मृणाल मीना, एडीएम श्री अनुकूल जैन, सीईओ स्मार्ट सिटी श्री आशीष पाठक एवं विभिन्न विभागों के अधिकारीगण मौजूद थे।

बन्दी की उपचार के दौरान मृत्यु

उज्जैन। केन्द्रीय जेल के अधीक्षक द्वारा जानकारी दी गई कि जेल में दण्डित बन्दी शंकरलाल पिता अमरसिंह उम्र 63 वर्ष निवासी शुजालपुर मंडी जिला शाजापुर को विगत 4 दिसम्बर को जेल चिकित्सक के परामर्श अनुसार एमव्हाय अस्पताल इन्दौर भेजा गया था। जहां उसे भर्ती कर उपचार दिया जा रहा था। सोमवार एक जनवरी को ड्यूटी पर तैनात जेल प्रहरी श्री जोगेन्द्र सिंह तोमर द्वारा सुबह 11.35 बजे दूरभाष पर गेटकीपर श्री संजय पाठक को सूचना दी गई।

उज्जैन में दो दिनों तक होगा सनातनी कुंभ

उज्जैन। बाबा महाकाल की नगरी में दो दिवसीय भव्य सनातनी कार्यक्रम, अखाड़ा परिषद अध्यक्ष और मुख्यमंत्री होंगे शामिल। उज्जैन। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में 3 और 4 जनवरी को सनातन कुंभ सा

को भव्य सनातनी कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जिसमें 3 जनवरी को प्रातः 9 बजे क्षीरसागर मैदान से भगवा सन्यास यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा कंठाल, सतीगेट, छत्री चौक, ढाबा रोड, दानी गेट, शिप्रा नदी की

फिरोजिया, विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, नगर निगम सभापति कलावती यादव सहित अन्य जनप्रतिनिधि और प्रमुख संत बढ़ाएंगे। गुरु माता मंदाकिनी पुरी ने धर्म प्राण जनता से अपील की है कि शोभायात्रा



नजारा नजर आएगा।

श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी द्वारा मालवा की प्रसिद्ध भागवत कथा आचार्य वर्षा नागर को निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर पद पर विभूषित किया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में 3 जनवरी को भव्य भगवा सन्यास यात्रा निकलेगी वहीं 4 जनवरी को महामंडलेश्वर पट्टाअभिषेक समारोह होगा जिसमें अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष सहित मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री और अन्य प्रमुख संत शामिल होंगे।

निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर गुरु मां मंदाकिनीपुरी ने बताया कि उज्जैन में 3, 4 जनवरी

छोटी रफ्त होते हुए कार्तिक मेला सदावल रोड स्थित कार्यक्रम स्थल मां अन्नपूर्णा प्रणावअक्षरधाम आश्रम पर पहुंचेगी। तत्पश्चात दोपहर 1 बजे शिप्रा नदी के रामघाट पर हवन मुंडन और सन्यास संस्कार कार्यक्रम संपन्न होगा। 4 जनवरी गुरुवार को साध्वी अन्नपूर्णा वर्षा जी का पट्टाअभिषेक समारोह दोपहर 12 बजे संत आशीर्वचन के माध्यम से संपन्न होगा। इस कार्यक्रम की शोभा अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रवींद्र पुरी महाराज, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव, शिव पंचायती अखाड़ा निरंजनी के सचिव श्रीमंत रामरतन गिरी महाराज, सांसद अनिल

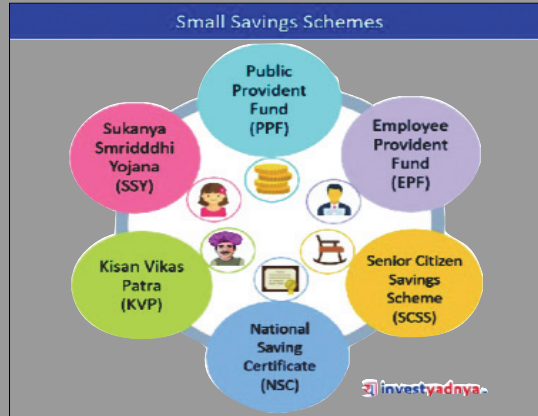
और पट्टाअभिषेक कार्यक्रम में शामिल होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ेगी।

3 और 4 जनवरी को आयोजित होने वाले सनातनी कुंभ में शामिल होने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्रीमहंत रविंद्र पुरी महाराज आज 2 जनवरी की रात को उज्जैन पहुंचेंगे।

अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के प्रवक्ता डॉ गोविंद सोलंकी ने बताया कि अखाड़ा परिषद अध्यक्ष एवं मां मनसा देवी ट्रस्ट हरिद्वार के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज सहित पट्टाअभिषेक समारोह में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव सहित अन्य अतिथियों को आमंत्रित किया गया है।

Public Provident Fund (PPF) पर नहीं मिलेगा ज्यादा ब्याज

छोटी बचत योजनाओं के लिए नई ब्याज दरों का ऐलान



31 दिसंबर 2023 पर सरकार छोटी बचत योजनाओं पर इंटरैस्ट रेट को रिवाइज करती है। ऐसी उम्मीद थी कि, सरकार छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज बढ़ा सकती है। स्मॉल सेविंग स्कीम की गिनती में पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम, पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट, PPF, NSC, KVP आदि इस गिनती में आते हैं

F.No.14/2019-NS
Government of India
Ministry of Finance
Department of Economic Affairs
(Budget Division)

North Block, New Delhi
Date: 29.12.2023

OFFICE MEMORANDUM
Subject: Revision of Interest Rates for Small Savings Schemes - reg.

The rates of interest on various Small Savings Schemes for the fourth quarter of financial year 2023-24 starting from 1st January, 2024 and ending on 31st March, 2024 have been revised as detailed below:

Instrument	Rates of interest from 01.01.2023 to 31.12.2023	Rates of interest from 01.01.2024 to 31.03.2024
Savings Deposit	4.0	4.0
1 Year Time Deposit	6.0	6.0
2 Year Time Deposit	7.0	7.0
3 Year Time Deposit	7.5	7.5
5 Year Time Deposit	7.5	7.5
5 Year Recurring Deposit	6.7	6.7
Senior Citizen Savings Scheme	8.2	8.2
Monthly Income Account Scheme	7.4	7.4
National Savings Certificate	7.7	7.7
Public Provident Fund Scheme	7.1	7.1
Kisan Vikas Patra	7.5 (will mature in 115 months)	7.5 (will mature in 115 months)
Sukanya Smriddhi Account Scheme	8.0	8.2

2. This has the approval of competent authority.

(Kapil Pathak)
Deputy Secretary (Budget)
Tele - 01123092649

Public Provident Fund (PPF) पर नहीं मिलेगा ज्यादा ब्याज

- छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में बदलाव।
- 3 साल की स्कीम पर ब्याज दर

0.1% बढ़ी, बढ़कर 7.1%

- सुकन्या समृद्धि योजना पर ब्याज दर 0.2% बढ़कर 8.2%
- जनवरी-मार्च तिमाही के लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी। लेकिन सुकन्या समृद्धि योजना में थोड़ा

ज्यादा ब्याज जरूर मिलेगा क्योंकि इसके लिए ब्याज दरें 8% से बढ़कर 8.2% कर दी गई हैं। बाकी छोटी बचत योजनाओं के लिए ब्याज दरों में कोई खास

बदलाव नहीं। सरकार ब्याज दर कैसे तय करती है?

- इन योजनाओं पर ब्याज दरें समान परिपक्वता की इन प्रतिभूतियों की उपज पर 0-100 आधार अंकों

के प्रसार पर सरकारी प्रतिभूतियों पर बाजार की पैदावार से जुड़ी होती हैं। जब सरकारी प्रतिभूतियों पर बाजार की पैदावार बढ़ती है, तो छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें भी बढ़ाई जानी चाहिए।

साइबर तहसील लागू करने वाला मध्यप्रदेश देश का एकमात्र राज्य

साइबर तहसील परियोजना पूरे प्रदेश में लागू होगी। 1 जनवरी, 2024 से साइबर तहसील की व्यवस्था मध्यप्रदेश के सभी 55 जिलों में लागू।

प्रदेश में बिना आवेदन, नामांतरण और अभिलेख दुरुस्तीकरण की फेसलेस की व्यवस्था जून, 2022 से लागू की गई है। इसे साइबर तहसील नाम दिया गया है। इसमें रजिस्ट्री उपरांत, क्रेता के पक्ष में अविवादित नामांतरण, एक फेसलेस, पेपरलेस तरीके से



ऑनलाइन प्रक्रिया के द्वारा 14 दिन में बिना आवेदन के और बिना तहसील के चक्कर लगाए स्वतः ऑटोमेटिक तरीके से हो जाता है और खसरे तथा

नक्षे में भी क्रेता का नाम चढ़ जाता है। वर्तमान में यह व्यवस्था प्रदेश के 12 जिलों की 442 तहसीलों में लागू है। इसके माध्यम से अब तक 16

हजार से अधिक प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है।

9 अक्टूबर, 2022 को मध्य प्रदेश के राजस्व और परिवहन मंत्री ने बताया कि सीहोर और दतिया जिलों से साइबर तहसील बनाने के पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद, इस नवाचार योजना का दूसरा चरण इंदौर, हरदा में भी लागू किया जा रहा है। साइबर तहसील लागू करने वाला मध्यप्रदेश देश का एकमात्र राज्य है, जिसने इस अभिनव प्रयोग से लंबित राजस्व प्रकरणों के निराकरण में

अप्रत्याशित सफलता प्राप्त की है।

ज्ञातव्य है कि साइबर तहसील का गठन अविवादित नामांतरण/बंटवारे के मामलों को आसानी से निपटाने के लिए किया गया था। जिस जिले में साइबर तहसील काम करेगी वहां के लोगों को अविवादित नामांतरण/बंटवारा के मामलों के लिए तहसील कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑनलाइन आवेदन करने से ऐसे अविवादित नामांतरण बंटवारा प्रकरणों का निराकरण हो सकेगा।

सेंसेक्स पहली बार 72,000 के पार

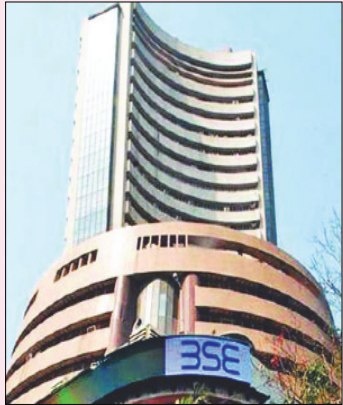
सेंसेक्स 40, 50 और 60 के स्तर पर अपने चरम पर था, क्या आपको तब निवेश करना बंद कर देना चाहिए था, आप 70 साहसिक कार्य पर नहीं गए होते। क्या आप अभी तक रुके हैं? यदि आप रुके होते तो क्या आपको इस रैली में शामिल न हो पाने का अफसोस नहीं होता?

आज सेंसेक्स 70 पर पिछले 5, 10, 15 और 20 वर्षों में उच्चतम बिंदु पर है। अगले 5, 10, 15, या 20 वर्षों के लिए, क्या यह चरम या निम्नतम बिंदु है?

1. बाजार की अस्थिरता कभी खत्म नहीं होती। जैसे ही हम 70 से आगे बढ़ेंगे, अगले पाँच, दस, पंद्रह और बीस वर्षों के लिए मार्केट की अस्थिरता निश्चित है। क्या आप अस्थिरता का अनुभव करने के

खिम् के बजाय विकास को खोना पसंद करेंगे?

70 के स्तर तक पहुंचने में, बाजार को कई गिरावट का सामना करना पड़ा है।



क्या आप मानते हैं कि आप गिरावट का पूर्वानुमान लगाने और गिरावट पर निवेश करने के लिए पर्याप्त चतुर थे? बाजार में समय बिताने से ज्यादा महत्वपूर्ण है अपना समय निवेश करना।

सेंसेक्स की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर लगभग 16.9% है। लगातार सकारात्मक रिटर्न की सबसे लंबी अवधि 1994 से 2003 तक थी, जो 9 वर्षों की थी।

2002 के बाद से, किसी भी 7-वर्ष की अवधि में एक भी वर्ष का रोलिंग रिटर्न नकारात्मक नहीं रहा है। जिसका अर्थ है कि यदि पैसा कम से कम 7 वर्षों के लिए निवेश किया गया था तो कोई नुकसान नहीं हुआ है।

जून 1996 में (26 वर्ष पहले) सेंसेक्स 3800 पर था। पिछले 26 वर्षों में, औसत इकटिटी म्यूचुअल फंड ने 18% प्रदान किया है।

महान निवेशक पीटर लिंग ने हमेशा धैर्य रखने के महत्व पर जोर दिया अक्सर, वर्षों के धैर्य का फल एक ही वर्ष में मिलता है।



उज्जैन। शहर में फिजिक्स वाला विद्यापीठ द्वारा कक्षा 9 से 12 वीं के विद्यार्थियों का काउंसलिंग सेशन आयोजित किया गया। इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षा कैसे उत्तीर्ण करें, फिजिक्स वाला विद्यापीठ के टीचर्स द्वारा इसका मार्गदर्शन किया गया। साथ ही NSAT स्कॉलरशिप टेस्ट में उत्तीर्ण बच्चों को पुरस्कार भी दिए गए। फिजिक्स वाला समूह के इस अनूठे इवेंट को बच्चों और उनके पैरेंट्स ने खूब सराहा।

